LOK SABHA

Saturday, March 18, 1967/Phalguna 27, 1888 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MEMBERS SWORN

Mr. Speaker: Secretary may call the names of Members who have not yet been sworn....

Shri P. K. Deo (Kalahandi): On a point of order, Sir. Before you take up the List of Business, I would like to point out....

Mr. Speaker: This is oath taking of Members who have not done so.

Shrimati Girji Kumari (Shahdol)

Shri Bhajahari Mahato (Purulia)

Mr. Speaker: Secretary to lay on the Table a copy of the President's address to both Houses of Parliament assembled together on the 18th March, 1967.

Shri P. K. Deo: Sir, before you proceed to the next item, I would like to point out that today being the last working day of the week, the Minister for Parliamentary Affairs should have come out with his statement regarding the business for the next week. We are kept absolutely in the dark. We do not know what is going to take place next week. In today's List of Business, I do not find any reference regarding the business of the next week. We would like to know about that.

Shri K. Lakkappa (Tumkur): Sir, I have given notice of an adjournment motion in respect of Rajasthan....

Mr. Speaker: They will come later on.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): The list of business for the next week will be presented to the House. First we are going to take up the President's Address. The Vote of Thanks will be moved and adopted After that, the Vote on Account will be taken up.

12.13 hrs.

PRESIDENT'S ADDRESS

Secretary: I lay on the Table a copy of the President's address to both Houses of Parliament assembled together on the 18th March, 1967.

President's Address

संसद् सदस्यगणं,

संसद् के दोनों सदनों के इस संयुक्त अधिवेशन में आप लोगों का स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नव-निर्वाचित तथा पुनर्निर्वाचित सदस्यों को मैं अपनी बधाई देता हू और जो लोग हमारे बीच इस सभा मे अब नही हैं उनको अपनी शुभकामनाएं।

2. पहले ऐसा विचार था कि इस महीने तीसरी लोक सभा का अन्तिम अधिवेशन खासतौर पर लेखानुदान पास करने के लिए बुलाया जाय। लेकिन अधिकांश चुनाव-परिणाम घोषित होते ही विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय सदस्यों ने हमसे यह आग्रह किया कि इस मौके पर नई लोक सभा का ही अधिवेशन बलाया जाय जिसमें लेखानुदान पास किया जाय और दूसरी आवश्यक कार्रवाई हो। सरकार इस राय से सहमत

हुई और उनकी सलाह पर तीसरी मार्च को तीसरी लोकसभा भंग कर दी गई।

3. हमारे चौथे आम चुनाव ने फिर से हमारे लोकतंत्र की शक्ति और सजीवता का सबूत पेश किया है। पिछले सभी आम चुनावों से अधिक मतदाताओं ने इस बार के निर्वाचन में भाग लिया। मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई। चुनाव शान्तिपूर्ण वातावरण में व्यवस्थित रूप से सम्पन्न हुआ, यद्यपि हिंसा और उपद्रव की कुछ दुःखद घटनाएं कहीं-कहीं हुई जिनकी सभी ओर से निन्दा की गई। आम चुनाव का काम जिस तरह पूरा हुआ उसके लिये मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। साथ साथ हमारी जनता भी बधाई की पात्र है, जिसने लोकतन्त्र और प्रतिनिधिक संस्थाओं के प्रति उत्साह, परिपक्वता और मर्यादा के साथ अपना विश्वास फिर से प्रकट किया।

4. स्वतंत्रता के बाद पहली बार केन्द्रीय सरकार से भिन्न राजनीतिक विचारधारा के दलों ने कई राज्यों में सरकार बनाई है। संघीय लोकतंत्रात्मक राज्य में यह कुछ अप्रत्याशित नहीं है। हमारे संविधान में संघ और राज्यों के पारस्परिक संबंधों के नियमन के लिये उपबन्ध है। इसके अलावा पिछले कई वर्षों के दौरान संघ और राज्य तथा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सहयोग, सद्भाव और सामंजस्यपूर्ण संबंध को सुदृढ़ बनाने के लिये कई संस्थाएं बन गई हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद्, जोनल काउन्सिलों और राज्यपालों तथा मुख्य मंत्रियों के समय-समय पर होने वाले सम्मेलन इसके विशेष उदाहरण हैं।

5. संघ सरकार संविधान के उपबन्धों का अक्षरशः बिना किसी भेदभाव और सही माने में पालन करेगी तथा राष्ट्रीय समस्याओं को सहयोग से हल करने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करेगी। हमें विश्वास है कि सभी राज्य इन संस्थाओं को कायम रखने में सहयोग देंगे तथा विचार-विमर्श द्वारा अपने और केन्द्र दोनों के हित में इनको अधिकाधिक उपयोगी बनायेंगे। देश की एकता और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, लोकतंत्रीय संस्थाओं को कायम रखना, आर्थिक विकास और जन-कल्याण हमारा परम उद्देश्य है और इस दिशा में संघ एवं राज्य को एक साथ मिलकर प्रयत्न करना है।

6. हमारी सरकार ने अभी अभी कार्य-भार संभाला है। मतदाताओं की इच्छा के अनुकूल नीति और कार्यक्रम तैयार करने और आपके सामने उन्हें प्रस्तुत करने में थोड़ा समय लगेगा। आर्थिक क्षेत्र में सरकार ने चार प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं:—

उन्होंने संकल्प किया है कि 1971 के अन्त तक खाद्य के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं रहें;

यह भी संकल्प किया है कि बुनियादी जरूरत की चीजों के मूल्य में अभिवृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने और कम से कम समय में स्थिरता प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाय;

तीसरा संकल्प यह है कि आर्थिक विकास की गति को पर्याप्त तीव्र करें ताकि 1976 तक विदेशी सहायता लेने की आवश्यकता न रहे;

और यह भी संकल्प किया है कि जन्म-दर प्रति हजार चालीस से घटकर यथाशीघ्र पच्चीस हो जाय, इसके लिए परिवार नियोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाय।

ये काम इतने बड़े और महत्वपूर्ण हैं कि सारी जनता और दलों के सक्रिय सहयोग और समर्थन के बिना पूरे नहीं हो सकते। इन्हें प्राप्त करना सरकार का प्रधान उद्देश्य होगा।

7. खाद्य समस्या का सामना करने के लिए संकटकालीन स्थिति की तरह जो कदम उठाये गये हैं, उन्हें और ज़ोरदार बनाया जायेगा। देश में अपनी पैदावार अथवा आयात से प्राप्त जो भी अनाज सुलभ है, हमें यह देखना है कि उनका वितरण समान रूप से हो। खाद्य के मामले में और कौन से काम करने हैं इसके सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार जानने तथा उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने पहले ही सम्पर्क किया है।

8 साथ ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार हर सम्भव प्रयत्न करेगी। आगामी प्रत्येक वर्ष में हमारे खाद्य आयात की मात्रा कम होती जानी चाहिये। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार काफी रासायनिक खाद और अच्छे बीज सुलभ कराने और किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था करने पर विशेष ध्यान देगी। लघु सिंचाई और कुओं को अधिक उपयोगी बनाने पर विशेष जोर दिया जायेगा। सिंचाई की जो बड़ी बड़ी योजनायें हैं और जिनके निर्माण का काम काफी आगे बढ़ चुका है उन को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रयत्न किया जायेंगे तथा सिंचाई के लिए देश में जो साधन सुलभ हैं उन के समुचित और सर्वाधिक उपयोग की व्यवस्था की जायेगी।

9. बारिश की कमी के कारण खेतों की पैदावार कम हुई और खासकर इसी वजह से पिछले दो वर्षों में कीमतें बढ़ती गई। समय पर बारिश न होने की वजह से औद्योगिक उत्पादन पर भी इसका असर पड़ा और औद्योगिक उत्पादन में कमी का एक कारण यह भी था कि विदेशी मुद्रा की कमी होने से आवश्यक कच्चा माल विदेश से मंगाया नहीं जा सका। केन्द्र द्वारा घाटे का बजट और राज्य सरकारों द्वारा रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष (ओवर ड्राफ्ट) के कारण स्फीति दबाव अधिक बढ़ा। इस स्थिति का सामना करने के लिए कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में पैदावार बढ़ाने के हर सम्भव उपाय किये जाने चाहियें। पिछले सालों में हमारी अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो साधन और क्षमता पैदा की गई है उसका अधिक से अधिक उपयोग करना है। इसके साथ ही वित्तीय अनुशासन सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिये। किफायतसारी और कुशलता में कोई विरोध नहीं है और सरकारी खर्च के हर क्षेत्र और हर दिशा में जितनी भी कटौती हो सकती हो की जानी चाहिये।

10 हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य है हमारी अर्थ व्यवस्था को आत्म-निर्भर और अधिक विकास के योग्य बनाना। इस लक्ष्य को 1976 तक प्राप्त कर लेने के लिये चौथी योजना में उन उद्योग धन्धों पर विशेष ध्यान दिया जायगा जिन से निकट भविष्य में हमारा तेजी के साथ विकास हो, विशेषतः ऐसे उद्योग धन्धे जो खेती और निर्यात में सहायक सिद्ध हों। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अधिक कार्यकुशलता पर सर्वाधिक जोर देना होगा। पहिली तीन योजनाओं में उद्योग धंधों के ऊपर काफी सरकारी पूंजी लगाई गई है और इस ख्याल से यह बहुत आवश्यक है कि इन उद्योग धंधों से ज्यादा मुनाफा हमें मिले ताकि विकास का काम आगे बढ़े। चौथी योजना की रूप-रेखा का मसौदा कुछ महीने पहले प्रकाशित किया गया था। सूखे के कारण जो असर देश पर पड़ा, कीमतों की जो प्रवृत्ति अभी है, देश और देश के बाहर से क्या अतिरिक्त साधन जुटाये जा सकते है, इन सब बातों को ध्यान में रख कर उस मसौदे का पुनरीक्षण किया जा रहा है और जल्दी ही राष्ट्रीय

विकास परिषद् से इस योजना के संबंध में विचार विमर्श करने के बाद संसद् के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जायेगा।

11. हमारी आबादी पचास करोड़ से आगे बढ़ गई है। यह एक खतरे की सूचक है और यदि हम इस ओर से बेपरवाह रहे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। राज्यो के साथ मिल कर परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सभी स्तरो पर सुदृढ बनाया जायेगा।

12. आर्थिक कठिनाइया तो एक कारण है, लेकिन इन के अलावा भी खासकर नौजवानो के बीच व्याप्त असतोष के कुछ और भी कारण हैं। आजादी के बाद जो एक नई पीढी पैदा हुई है उस के मन में कुछ नये विचार और नई आकाक्षाये है। हमे उन की ओर ध्यान देना आवश्यक है। शिक्षा आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उन के सम्बन्ध मे राज्यो के विचार मागे गये हैं और उन सिफारिशो को ध्यान में रखते हुए हमारी शिक्षा-पद्धति को पुनर्गठित करना जरूरी है। विश्वविद्यालय स्तर पर एक राष्ट्रीय सेवा की योजना के सम्बन्ध में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

13 हमारी सभी योजनाओ और प्रायोजनाओं की सफलता हमारे प्रशासन की कुशलता और सत्य निष्ठा पर निर्भर करती है। काम मे कुशलता लाने के लिए प्रशासनिक ढांचे मे परिवर्तन किये जायेगे। योजना आयोग का पुनर्गठन होगा। अभी जो नियत्रण लागू किये गये है उन का पुनरीक्षण किया जायेगा और उन मे से जो अनावश्यक होंगे उन्हें हटा दिया जायेगा तथा नियंत्रण को अधिक कुशल और उपयोगी बनाने के लिए उनको फिर से समजित किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार के पुनर्गठन के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें शीघ्र ही प्राप्त होने वाली हैं।

14. सार्वजनिक जीवन और सरकारी कर्मचारियो के आचरण में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सच्चे लोकतंत्र की आधारशिला हैं। इस विषय पर प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक अन्तरिम रिपोर्ट दी है। सरकार आयोग की इस सिफारिश को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करती है कि ऊंचे राजनीतिक अथवा प्रशासनिक पदो के भ्रष्टाचार की समस्या को दूर करने के लिए समुचित सस्था के गठन की आवश्यकता है। सरकार शीघ्र ही इस विषय मे अपने प्रस्तावो को तय कर ससद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। उन्होने आयोग की उन सिफारिशो को जिनका राज्य सरकारो से सम्बन्ध है, उन्हें भेज दिया है।

15 श्रम के सम्बन्ध मे श्री गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता मे एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया है। ग्रामीण श्रमिको सहित सभी प्रकार के श्रमिको के आजादी के बाद के काम और रहन-सहन के हालात का पुनरीक्षण कर यह आयोग समुचित सिफारिश करेगा। सघ की राजभाषा के सम्बन्ध मे दिये गये आश्वासनो को सावैधिक स्वीकृति देने के लिए शीघ्र ही ससद मे विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। जो घोषणा पहिले की जा चुकी है उस को ध्यान मे रखते हुए गोवध पर प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जायगी. जैसा कि घोषित किया जा चुका है असम के नेताओ से हुए विचार-विमर्श को ध्यान मे रखते हुए असम राज्य के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी। राज्य सरकारो से परामर्श कर वित्तीय वर्ष को बदलने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा।

16. आज के ससार मे कोई भी देश अलग नही रह सकता। भारत को विश्व-कुटुम्ब मे अपना समुचित स्थान लेना है। सुरक्षा परिषद में हमारी सदस्यता से हम पर

कुत्तर उत्तरदायित्व आ गया है, जिसे निभाने का हम भरसक प्रयत्न करेंगे"।

17. भारत की विदेश नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी है। भारत ने जिस शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व को भावना को प्रवर्तित करने के लिए जितना भी कार्य किया है, उसे अब दोनो गुटो के नेताओ ने स्वीकार कर लिया है। अमरीका और रूस दोनो देशों के साथ हमारे विशेष मित्रतापूर्ण सम्बन्ध है। हमारी गुट-निरपेक्षता की नीति सफल प्रमाणित हुई है। सरकार इस नीति को सुदृढ बनाने का हर सम्भव प्रयत्न करेगी और उसके भावात्मक सिद्धान्तो पर सकल्प के साथ चलती रहेगी।

18 आज मानवता के सामने दो सकट विद्यमान है। एक है निर्धन राष्ट्रो और धनी राष्ट्रो के बीच बढ़ती हुई खाई। दूसरा है कुछ देशो द्वारा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त का अस्वीकार।

19 सरकार की विदेश नीति के दो उद्देश्य होगे। हमारे राष्ट्रीय हितो—आर्थिक, राजनीतिक और रक्षा सम्बन्धी हितो—को आगे बढाना और अतर्राष्ट्रीय सहयोग का सवर्धन। इस उद्देश्य की प्राप्ति मे, हम ससार के अधिकाश देशो के साथ अधिकाधिक मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाने और उन्हे कायम रखने मे सफल हुए है। भारत के अन्य एशियाई देशो के साथ सम्बन्ध सुदृढ करने का सरकार का विशेष प्रयत्न रहेगा।

20 यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे मित्र देश बर्मा की सरकार के साथ हमारी सरकार, हमारी परम्परागत सीमा का औपचारिक सीमाकन सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर करने मे सफल हुई है।

21. सरकार वियतनाम सम्बन्धी अपनी नीति पर दृढ़ है, जिसका अनेक बार स्पष्टीकरण किया जा चुका है।

22 पाकिस्तान सरकार और वहा के लोगों की मित्रता और सहयोग प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार हृदय से इच्छुक है। सामान्य हित रखने वाले हमारे इन दोनो देशो को जिस कटुता और सघर्ष ने कभी-कभी विलग कर दिया है उससे हमे सबसे अधिक दुख पहुचा है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सद्भावना, मित्रता और सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिए हमारी सरकार भरसक प्रयत्न करेगी।

23 हम चीन के साथ भी शांति से रहना चाहते हैं। परन्तु चीन सरकार की आक्रामक कार्रवाई और गतिविधि और साथ ही उसके द्वारा शातिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना की अस्वीकृति—ये बडी कठिनाइया चीन के साथ हमारे सम्बन्ध सुधारने मे बराबर बाधक बनी हुई हैं।

24 ससार के जिन मित्र राष्ट्रो, अतर्राष्ट्रीय सस्थाओ तथा अभिकरणो ने हमारे विकास कार्यक्रमो मे तथा हमारे खाद्यान्न सकट को दूर करने मे हमे अमूल्य सहायता प्रदान की है, उनके हम आभारी हैं।

25 विकासशील देश भी अपनी अर्थ-व्यवस्थाओ को, आपसी सहयोग द्वारा सुदृढ कर सकते हैं। युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, सयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नासर और हमारे प्रधान मत्री—इन तीन गुटनिरपेक्ष देशो के नेताओ के त्रिपक्षीय सम्मेलन ने इस दिशा मे कार्य करने का आधार स्थापित कर दिया है।

26 हाल ही मे हमे एक और राष्ट्र के अध्यक्ष, अफगानिस्तान के महामान्य सम्राट, के स्वागत करने का अवसर मिला जिनके साथ हमारी बहुत ही मित्रतापूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई।

27 ससद् सदस्य, आज हमारे सम्मुख जो प्रश्न हैं उनमे से कुछ का मैंने सक्षेप में उल्लेख किया है। इन विषयो मे तथा अन्य

विषयों में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की पूरी जानकारी प्राप्त करने का आपको यथासम्भव अवसर मिलेगा। आपका वर्तमान सत्र छोटा ही होगा, जो कुछ अनिवार्य वित्तीय और बजट सम्बन्धी कार्यवाही तक सीमित रहेगा। आगे की कार्यवाही पर विचार करने के लिए आप फिर से शीघ्र ही मिलेंगे।

28. वर्तमान सत्र में निम्नलिखित अध्यादेशों का स्थान लेने के लिए विधेयक प्रस्तुत किये जायेंगे :—

(1) खनिज उत्पादन (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) संशोधन अध्यादेश, 1966,

(2) अत्यावश्यक वस्तुयें (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1966,

(3) भूमि अर्जन (संशोधन तथा मान्य) अध्यादेश, 1967, और

(4) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1967।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) स्थिरता विधेयक भी प्रस्तुत किया जायेगा।

29. 1967–68 के वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार के अनुमानित आय और व्यय का विवरण आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

30. यह हमारे लिए दुख का विषय है कि राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा। हमारी हार्दिक आशा है कि इस व्यवस्था को अधिक समय तक बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा। और शीघ्र ही उत्तरदायी सरकार फिर से स्थापित करना सम्भव होगा। 1967–68 के वित्त वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के अनुमानित आय और व्यय का विवरण भी आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

31. संसद सदस्य, मेरी शुभकामना है कि आप अपने प्रयास में सफल हों।

[Members of Parliament,

It gives me great pleasure to welcome you to this joint session of the two Houses of Parliament. I offer my congratulations to the newly elected and re-elected Members and my good wishes to those no longer with us.

2 Earlier, it was intended that the third Lok Sabha should have a final session this month mainly to pass a Vote on Account. Shortly after most of the election results were announced, many Honourable Members from different political parties approached us with the request that it should be the new Lok Sabha which should meet at this juncture to pass the Vote on Account and to transact other essential business. The Government agreed with this view and, on their advice, the third Lok Sabha was dissolved on the 3rd of March.

3. Our fourth General Elections have once again demonstrated the vigour and vitality of our democracy. There was a larger turn-out of voters than on any previous occasion, as well as a substantial increase in the number of women who cast their votes. Despite a few unfortunate incidents of violence and disturbance which have been universally condemned, the elections were orderly and peaceful. The Chief Election Commissioner and his staff deserve our congratulations. So do the people, for the enthusiasm, maturity and dignity with which they have reaffirmed their faith in democracy and representative institutions.

4. For the first time since Independence, Governments of political complexions different from that of the Government at the Centre have been formed in several States. In a federal democratic polity, this is to be expected. Our Constitution has pro-

visions defining and regulating the relationship between the Union and the States and their mutual obligations. Further, over the years, we have developed certain institutions for promoting co-operation, understanding and harmonious relations between the Union and the States, and between one State and another. The National Development Council, the Zonal Councils and periodic conferences of Governors and Chief Ministers are the more conspicuous examples of this nature.

5. The Union Government will respect the constitutional provisions in letter and in spirit without any discrimination and endeavour to strengthen the arrangements for a co-operative approach to our national problems. We are sure that all States will extend their co-operation in preserving these institutions and in making their deliberations increasingly fruitful and beneficial both to the Union and to themselves. Strengthening the unity of the country, safeguarding its security, preserving democratic institutions, and promoting economic development and the well-being and happiness of all our people are the common objectives towards which the Union and the States must strive together.

6. Our Government have just taken office. While they will take a little time to place before you all the policies and programmes which they will pursue in accordance with the mandate of the electorate, they have already decided upon four major objectives in the economic sphere.

(1) They have resolved to end our dependence on food assistance from abroad by the end of 1971.

(2) They have resolved to do all that is possible to ensure that the rising trend in prices of the basic necessities of life is halted and conditions of stability achieved in the shortest possible time.

(3) They have resolved to attain and sustain an adequate rate of economic growth so as to eliminate the need for external economic assistance by 1976.

(4) And they have resolved to pursue the national programme of family planning with the objective of reducing the birth rate from forty per thousand to twenty-five per thousand as expeditiously as possible.

These tasks are of such magnitude that they can be accomplished only with the active support, participation and involvement of the people and the co-operation of all parties. To secure these wi l be one of Government's primary objectives.

7. The food situation will be dealt with on an emergency basis. The measures already set in motion to fight the drought will be strengthened. We have to ensure that the available foodgrains in the country, whether indigenous or imported, are distributed equitably Government are already in touch with State Governments seeking their views and their co-operation in regard to the further steps that have to be taken on the food front.

8 Simultaneously, Government intend, in collaboration with the States, to make every effort to augment agricultural production. Our food import requirements must be reduced in each successive year. Towards this end, Government will pay special attention to the adequate availability of fertilizers and improved seeds and to the credit needs of the farmer Greater emphasis will be placed on minor irrigation and energisation of wells. Efforts will be made to expedite the completion of major irrigation projects that are in an advanced stage of construction and to ensure the fullest utilization of the irrigation potential already created.

9. The upsurge in prices, particularly during the last two years, was primarily the result of the shortfall in

agricultural production due to the failure of the monsoons. Industrial production too was affected by the failure of the monsoons and the shortage of foreign exchange to import necessary raw materials. Deficit financing at the Centre and overdrafts by the State Governments on the Reserve Bank further aggravated the inflationary pressures. To deal with the situation, everything possible must be done to increase production in both agriculture and industry. The considerable potential and capacity in various sectors of the economy built during the past years must be more fully utilised. Simultaneously, a stricter financial discipline must be maintained. Economy is not inconsistent with efficiency and we must seek genuine economy in every field and in every sector of public expenditure.

10. Our Five-Year Plans have had the objective of making the economy self-reliant and capable of further development. To achieve this target by 1976, special attention will be paid in the Fourth Plan period to those industries which will contribute most to rapid development in the immediate future, particularly industries which will be helpful to our agriculture and exports. The greatest emphasis will have to be laid on higher efficiency in both the public and the private sectors. Substantial investments have been made in industry by the public sector in the first three Plans and it is important that these are now made to yield greater profits to sustain further development. The Draft Outline of the Fourth Plan was published some months ago. It is being reviewed in the light of adverse effects of the drought, the latest price trends, and the prospects of mobilising additional resources, internal and external, and it is proposed to take an early opportunity to discuss the Plan fully in the National Development Council and thereafter in Parliament.

11. Our population has crossed the five hundred million mark. This is a danger signal which we can ignore only at our peril. Family Planning programmes will be strengthened at all levels with the co-operation of the States.

12. Although economic difficulties are at the root of much of the prevailing discontent, other factors too have contributed to a sense of frustration, particularly among the young. The new generations which has grown up since Independence has new aspirations and new ideas. We must respond to them. The educational system needs re-shaping in the light of the recommendations of the Education Commission, on which we are awaiting the comments of the State Governments. A new scheme of national service at the University level is under active consideration.

13. The success of all our Plans and projects depends upon the efficiency and integrity of the administration. To ensure efficiency in performance, changes will be made in the administrative set-up. The Planning Commission will be re-organized. The working of controls will also be reviewed; those found unnecessary will be withdrawn and others re-adjusted as may be required to make them more purposeful and efficient. The Administrative Reforms Commission is expected to submit its recommendations on the re-organisation of the Central Government fairly soon.

14. Integrity and impartiality in public life, and in the conduct of the public servants, are the foundations of true democracy. The Administrative Reforms Commission has made an interim report bearing on this subject. Government agree, in principle, with the Commission's approach on the need for adequate and satisfactory institutional arrangements to deal with problems of corruption in high public office, whether political or administrative. They expect to finalize their proposals and place them before Parliament at an early date. They have already referred to the State Governments the recommendations of the Commission which concern them.

15. A National Commission on Labour has been set up under the chairmanship of Sri Gajendragadkar. The Commission will review and make appropriate recommendations on the whole field of the working and living conditions of labour of all categories, including rural labour, since Independence. Legislation to give statutory recognition to the assurances given in regard to the official language of the Union will be shortly introduced in Parliament. A high-level committee will be set up to examine the question of a ban on cow slaughter in terms of the announcement already made. A committee will also be set up, as announced, to examine further the proposal for the re-organisation of the State of Assam in the light of the discussions held with the leaders of Assam. The question of changing the financial year will be considered in consultation with the State Governments.

16. In a shrinking world, no country can remain isolated. India has a role to play in the counsels of the world. Our membership of the Security Council casts on us an onerous responsibility which we shall do our best to discharge.

17 The foreign policy of India has stood the test of time. The concept of peaceful co-existence, which India had done so much to sponser, is now accepted by the leaders of the two groups. With both the United States and the Soviet Union we have the friendiest of relations. Our policy of non-alignment stands vindicated. Government will do everything possible to strengthen non-alignment and pursue the positive aspects of this policy with vigour and determination.

18. There are two dangers which confront humanity today. One is the widening gulf between the poor nations and the rich nations. The other is the rejection of the principle of peaceful co-existence by some countries.

19. Government's foreign policy will serve the twin objectives of furthering our national interests—economic, political and strategic—and of promoting international co-operation. Towards this end, we have succeeded in building up and maintaining the friendliest of relations with most countries of the world. It will be Government's special endeavour to strengthen India's relations with our Asian neighbours.

20. It is a matter of deep gratification that our Government have been able to sign an Agreement with the Government of Burma about the formal delineation and demarcation of our traditional boundary with that friendly country.

21 Government adhere to their policy regarding Vietnam which has been enunciated on several occasions.

22 Government most sincerely desire the friendship and co-operation of the Government and people of Pakistan Nothing has distressed us more then, the bitterness and conflict which have sometimes divided our two countries which have many common interests Government will make every effort to achieve a relationship of the fullest understanding, goodwill and amity with Pakistan.

23. With China too we would like to live in peace. But the aggressive acts and postures of the People's Republic of China coupled with their rejection of the concept of peaceful co-existence, continue to be the major obstacles to an improvement of our relations with China.

24. We are grateful to friendly nations of the world, as well as to inernational institutions and agencies, who have given us valuable assistance in our development programmes as well as in meeting our food crisis

25. Developing countries can also strengthen their economies through mutual co-operation. The Tripartite Meeting between the leaders of three non-aligned countries, President Tito of Yugoslavia, President Nasser of the United Arab Republic and our Prime Minister, has laid the foundations of such an approach.

26. Another Head of State whom we had the pleasure of welcoming amidst us recently was His Majesty the King of Afghanistan, with whom we have had very friendly and cordial talks.

27. Members of Parliament, I have briefly touched upon some of the issues that confront us today. You will have an opportunity to get a fuller picture of the Government's policies and programmes in these and other matters in due course. Your present session will be a short one, confined to the transaction of certain essential financial and budgetary business. You will be meeting again shortly to consider further business.

28. Bills will be introduced in the current session to replace:—

(1) The Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Amendment Ordinance, 1966;

(2) The Essential Commodities (Second Amendment) Ordinance, 1966;

(3) The Land Acquisition (Amendment and Validation) Ordinance, 1967; and

(4) The Representation of the Peop e (Amendment) Ordinance, 1967.

The Armed Forces (Special Powers) Continuance Bill will also be introduced.

29. A statement of the estimated receipts and expenditu e o. the Government of India for the financial year 1967-68 will be laid before you

30. It is a matter of distress to us that President's rule had to be introduced in Rajasthan. It is our earnest hope that it will not be necessary to continue this arrangement for long and that it will be found possible early to restore responsible government.

A statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of Rajasthan for the financial year 1967-68 will also be laid before you.

I wish you success in your endeavours.

12.13½ hrs.

OBITUARY REFERENCES

Mr. Speaker: I have to inform the House of the sad demise of eight of our friends, namely Shri Sadashiv Govind Barve, Dr. Gopichand Bhargava, Dr. Lanka Sundaram, Shri Radhelal Vyas, Shri Algu Rai Shastri, Shri Sadath Ali Khan, Shrimati V. Vimla Devi and Shri Apurva Kumar Chanda.

Shri Sadashiv Govind Barve was elected to this House from the Bombay North East Constituency of Maharashtra. He passed away at New Delhi on the 6th March, 1967 at the age of 52.

Dr. Gopichand Bhargava was a Member of the Constituent Assembly of India during the year 1946. He passed away at Chandigarh on the 26th December, 1966 at the age of 78.

Dr. Lanka Sundaram was a Member of the First Lok Sabha during the years 1952—57. He passed away at New Delhi on the 8th January, 1967 at the age of 63

Shri Radhelal Vyas was a Member of the Provisional Parliament, First Lok Sabha, Second Lok Sabha and Third Lok Sabha during the years 1950—67. He passed away at Indore on the 13th January, 1967, at the age of 59.

Shri Algu Rai Shastri was a Member of the Constituent Assembly of India, Provisional Parliament and First Lok Sabha during the years 1946—57. He passed away at Lucknow on the 12th February, 1967, at the age of 67.